and State sector? pertaining to tobacco growers and cultivation in the country such as production, marketing, quality, price, export market, seed requirements etc. and recommend measures to increase production and profit from the crop to the growers. It facilities coordination between research and development programmes relating ot tobacco and advice Government for improvement of quality and productivity of tobacco and other related matters as may be i necessary from time to time. The Council is managed by the Ministry of Agriculture, Govt. of India.

(b) Central Tobacco Research Institute has a) management committee which meets once in a year. Its latest meeting was hold on 2-7-92. Indian Tobacco Development Council does not have a management Committe*, However, its members meet periodically. They last met on 11-1-89 at Hyderabad.

(c) At present, Central Tobacco Research Institute has 592 staff members. Its plan expenditure during 1989-90, 1990-91 and 1991-82 was Rs. 49.91 lakhSj, Rs. 15.98 lakhs and Rs. 94.49 lakhs respectively. The non-plan expenditure during these three years was Rs. 248.78 lakhs, Rs. 278.95 lakhs and Rs. 285.90 lakhs respectively.

Tobacco Development Council is provided with secretarial assistance by the Directorate of Tobacco Development. whenever it is necessary. No separate budgetary allocation is made either under plan or non-plan for Council by the government. A sum of Rs. 11,177 was spent on account of travelling allowance and daily allowance during 1989 meeting.

**हिमाचल प्रदेश को मल निकासी योजनाओं के लिए अनुदान**

159. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1992-93 के दौरान किन-किन नगरों में मल निकासी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान की मांग की है;

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं?

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** :(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 शहरों अर्थात् शिमला, मनाली, मंडी, धर्मशाला, चम्बा और सोलन के एकीकृत विकास हेतु बाह्य सहायता के लिये मल जल निर्यास घटक के लिये 42.30 करोड़ रु. सहित 102.40 करोड़ रु. अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मल जल निर्यास के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विद्यालयों में बड़ी संख्या में अधर में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के बारे में चिन्ता**

*160. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :
**श्री राम जेठमलानी** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1992 के इकोनामिक टाइम्स में ?"हाई ड्राप आउट रेट ब्लेम्ड फार लिटरेसी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट में हमारे देश में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर पढ़ाई को अधर में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए और अधिक निधियां आवंटित करने के बारे में भी सिफारिश की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) "हाई ड्राप आउट रेट्स ब्लेम्ड फार इलिटरेसी" शीर्षक से एक रिपोर्ट दिनांक 16 जून, 1992 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक क्षेत्रीय तथा अंचलिक अध्ययन ने "एजूकेशन इन एशिया कम्पेरेटिव इस्टडी आफ कास्ट एंड फाइनेन्सिंग" (1992) में अन्य बातों के साथ-साथ प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में पढाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों की समस्या का हवाला दिया है तथा इसके लिए पर्याप्त आवंटन की आवश्यकता पर बल देते हुए इस क्षेत्र में व्यय की सार्थकता का विश्लेषण किया है ।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों में पर्याप्त कमी देखी गई है । वर्ष 1979-80 में प्राइमरी में 58.8% तथा उच्च प्राइमरी में 72.7% से वर्ष 1987-88 में यह क्रमशः 46.97% तथा 62.29% तक कम हुई है । वर्ष 1987-88 में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वाले छात्रों की दर 75.30% थी । बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए सतत प्रयास किए गए हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत शिक्षण-अध्ययन उपस्कर अतिरिक्त शिक्षकों तथा उपयुक्त भवनों का प्रावधान किया गया है । अनौपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जा रहा है । बाल केन्द्रित तथा क्रियाकलाप-आधारित अध्ययन पर बल दिया गया है तथा तदनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्य सामग्री तैयार की गई है । स्कूल-शिक्षकों के लिए सेवाकालीन तथा सतत शिक्षा का एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए आवंटन को छटी योजना में 30% से बढाकर आठवीं योजना में 38.7% कर दिया गया है । इस समय 2,880 करोड़ रु. आवंटित किये गये हैं तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में समायोजन करके योजना-अवधि के दौरान अतिरिक्त निधियां भी प्रदान की जा सकती हैं । आठवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा के लिए 1519 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है ।

**Implementation of Intensive Cotton Development Programme**

@851. DR ABRAR AHMED:
SHRI SURESH KALMADI; Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved implementation of the Intensive Cotton Development Programme in some States during the year 1992-93; and

(b) if so, what is the total outlay-earmarked for this centrally sponsored programme and the names of the States involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) The total outlay earmarked for this programme during 1992-93 is Rs. 1976.96 lakhs. The programme is being implemented in the following States:—

1. Andhra Pradesh
2. Gujarat
3. Haryana
4. Karnataka
5. Madhya Pradesh
6. Maharashtra
7. Orissa
8. Punjab
9. Rajasthan
10. Tamil Nadu
11. Uttar Pradesh

@ Previously Unstarred question, 434, transferred from 13th March 92